झूठ बोले कव्वा काटे काले कव्वे से डरियो....

पेज एक का शेष

दो यूनिवर्सिटी और खोलने के जुमले छोड़ रही है। दुधोला वाली उक्त यूनिवर्सिटी के अलावा एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और खोलने का ढोल पीटा जा रहा है।

बेरोजगारी की हालत यह है कि इन्जीनीयरिंग की डिग्री डिप्लोमा लिये नौजवान एस्कार्ट जैसी कम्पनियों में ट्रेनी के नाम पर लोहा ढो रहे हैं मात्र 10-12 हजार मासिक वेतन पर। उन्हें यह कच्ची नौकरी भी बिना सिफ़ारिश के नहीं मिलती। इन हालात में जुमलेबाज़ों की यह सरकार जुमले छोड़ रही है कि उक्त कौशल यूनिवर्सिटी में 10 हजार मासिक की छात्रवृति देने की, आखिर किसको बेवकूफ़ बना रही है सरकार?

36 करोड़ में 50 बेड का मल्टी स्पेशिलटी अस्पताल

भारत सरकार द्वारा एक हज़ार करोड़ की लागत से बनाया गया ईएसआईसी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज जिसके चलाने पर सालाना 150 करोड़ का खर्चा भी आ रहा है वहां आज तक मल्टी स्पेशिलटी सेवायें उपलब्ध नहीं हैं। मल्टी स्पेशिलटी तो छोड़िये आईसीयू तक की सुविधा नहीं है। डायलेसिस तक का काम भी ठेके पर चला कर मज़दूरों को धोखा दिया जा रहा है। इसी अस्पताल से जो मरीज़ सुपर स्पेशिलटी के लिये प्राइवेट अस्पतालों को रैफ़र किये जाते हैं उस पर 30 करोड़ का सालाना खर्च करना मंजूर है पर अपने यहां वे सुविधायें उपलब्ध नहीं करायेंगे।

उक्त 30 करोड़ तो अकेले एनएच-3 स्थित मेडिकल अस्पताल का रैफ़रल बिल है। सेक्टर 8 स्थित ईएसआई अस्पताल का बिल तो 40 करोड़ से भी अधिक जा रहा है। यह सब तो तब है जब इएसआई कार्पोरेशन के पास धन की कोई कमी नहीं। मज़दूरों के वेतन से हर माह साढे छः प्रतिशत काट-काट कर आज निगम के खजाने में एक लाख करोड़ से अधिक रकम जमा पड़ी है, परन्तु इसे मज़दूरों पर खर्च करने में सरकार की जान निकलती है।

ओल्ड फ़रीदाबाद में जो 50 बेड का अस्पताल खोलने के जुमले फ़ेंक रहे हैं क्या उन्हें सेक्टर 8 में बनी खड़ी ईएसआई की वह बिल्डिंग नज़र नहीं आती जिसमें 200 बेड का अस्पताल चलाया जा सकता है जबकि वहां मात्र 50 बेड का ही चलाने का ढोंग किया जा रहा है? इससे भी बुरी बात तो यह है कि 50 बेड में से भी 40 खाली पड़े रहते हैं क्योंकि वहां न तो डॉक्टर व अन्य स्टाफ़ है न कोई आवश्यक उपकरण, ऐसे में भला वहां मरने कौन आयेगा?

36 करोड़ की बिल्डिंग बनाने वाली सरकार से जनता पूछ रही है कि ज़िले भर में जितने भी अस्पताल, डिस्पेंसरियां हेल्थ सेंटर व डिलिवरी हट खड़े कर रखे हैं उनकी क्या स्थिति है? कहीं पर भी न डॉक्टर हैं न स्टाफ़ पर्याप्त। डॉक्टरों की तो बात छोड़िये नार्मल डिलिवरी कराने वाली नर्स अथवा दाई तक के अभाव में आये दिन इन अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के दरवाजों पर डिलिवरी हो रही हैं। ज़िले का सबसे बड़ा एवं पुराना बीके अस्पताल, इलाज कम और दिल्ली के लिये रैफ़र अधिक करता है क्योंकि वहां न तो पर्याप्त डॉक्टर और स्टाफ़ है और न ही आवश्यक साजो सामान।

संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि सेक्टर 30, सेक्टर 3 व 55 में अस्पतालों के नाम पर बनी खड़ी बिल्डिंगों का कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री गूजर जी तिगांव में एक बड़े हैल्थ सेंटर की बिल्डिंग की आधारशिला रख कर आये हैं जबकि स्टाफ़ वहां पहले से मौजूद सेंटर के लिये भी पर्याप्त नहीं है। कुल मिला कर सारा खेल शिलान्यास और नारियल फ़ोड़ कर जनता को बेवकूफ़ बनाने तक ही सीमित है। इसके अलावा इन नेताओं ने करना धरना कुछ नहीं।

ओल्ड फ़रीदाबाद के इसी अस्पताल के साथ पहले से बने सरकारी स्कूल का काया-कल्प करके उसे आधुनिक निजी स्कूलों जैसा बनाने का जुमला भी उछाला जा रहा है, इसके विपरीत ज़िले क्या राज्य भर के स्कूलों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। किसी भी स्कूल में न तो पर्याप्त स्टाफ़ है न बैठने, पेयजल व शौचालय की उचित व्यवस्था है। इसी के चलते परीक्षा परिणाम लगातार जीरो से दस प्रतिशत तक ही सिमट जाता है। इन्हें सुधारने के नाम पर हर साल जांच बैठाने का नाटक खेला जा रहा है। दूसरी ओर जब इन स्कूलों में दाखिला लेने की बजाय छात्र निजी स्कूलों में जाने लगते हैं तो सरकार छात्रों के अभाव का बहाना लेकर स्कूलों को ही बंद कर देती है। इसी कड़वी सच्चाई को छिपाने के लिये स्थानीय सांसद एवं मंत्री जी ओल्ड फ़रीदाबाद में आधुनिक स्कूल खोलने का छालावा पेश कर रहे हैं।

FASHION.IN

Available all types of ladies cotton kurties, Fancy Kurties, Jegin, legin, Fancy Top, T-Shirts, Trousers and imported material in wholesale price.

SPECIALITY IN FANCY TOP & FANCY KURTIES

लेडीज कपड़ों पर भारी छूट

एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

Address : 5M/22, N.I.T. FARIDABAD NEAR DAYANAND WOMEN COLLEGE, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL ROAD . 9911489490

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोग़ों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100-500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

बिना प्रिंसिपल के डीएवी कॉलेज

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 18-24 नवम्बर 2018 के अंक में राजनीतिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक, आर्थिक व सामाजिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी परंतु अदालत द्वारा सबूतों के अभाव में बरी विनायक दामोदर सावरकर की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका को दो पक्षों में मूल्यांकन किया जा सकता है-पहला सावरकर के अंडमान जेल जाने से पूर्व तथा दूसरा अंडमान जेल जाने के बाद। सावरकर ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संस्था 'अभिनव भारत' तथा लंदन में प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित 'इंडियन होम रूल सोसाइटी' के तत्वावधान में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। नासिक के कलैक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में सावरकर को 1990 में लंदन से लाकर भारत में उन पर नासिक षडयंत्र केस चलाया और आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया।

अंडमान जेल की यातनाओं से तंग आकर सावरकर ने 1911, 1913, 1917 व 1920 में कुल चार माफ़ीनामे अंग्रेज अधिकारियों को लिखे, जिनका 'सावरकर ने अंग्रेजों से क्या माफ़ी मांगी थी?' में खुलासा किया गया है। सावरकर द्वारा लिखी याचिका का एक महत्वपूर्ण अंश ध्यान देने योग्य है कि: 'अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेजों के प्रति वफ़ादार रहूंगा, जो कि विकास की सबसे पहली शर्त है। इससे भी बढ़कर संविधानवादी रास्ते में मेरा धर्म परिवर्तन सभी भटके हुये नौजवानों को सही रास्ते पर लायेगा, जो कभी मुझे अपने पथ-प्रदर्शक के तौर पर देखते थे। मैं भारत सरकार, जैसा चाहे, उस रूप में सेवा करने के लिये तैयार हूं। आशा है, हुजूर मेरी याचनाओं पर दयालुता से विचार करेंगे। इसी कारण अंडमान जेल से रिहा होने के बाद सावरकर ने ब्रिटिश को दिये अपने आश्वासन को पूरी ईमानदारी से निभाया और ब्रिटिश राज के विरुद्ध किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया व एक तरह से ब्रिटिश सरकार के समर्थक बने रहे।

'मज़दूर मोर्चा का आंकलन सही सिद्ध हुआ-फसल बीमा योजना एक बड़ा मोदी घोटाला 85 लाख किसान निकले शिकंजे से' में मोदी सरकार की फ़सल बीमा योजना घोटाले का पर्दाफ़ाश किया गया है। मोदी सरकार ने फसल बीमा योजना का व्यापार सरकारी बीमा कम्पनियों को न देकर निजी कम्पनियों को दिया। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र की दस बीमा कम्पनियों ने बीते दो साल में कुल 15,795 करोड़ रुपये कमाये। इस योजना की खासियत यह रही कि किसानों से बगैर पूछे उनके बैंक खातों से फ़सल बीमा की किश्त के रूप में एक रकम बैंक मैनेजर द्वारा काट ली जाती थी और इस रकम के अलावा सब्सिडी के तौर पर किश्त का एक बड़ा हिस्सा राज्य व केन्द्र सरकार बीमा कम्पनी को भुगतान करती थी।

लोकसभा के आगामी चुनावों के मद्देनज़र जनता को लुभाने के लिये मोदी सरकार ने 'आयुष्मान भारत' योजना घोषित की जिसके तहत 50 करोड़ अति गरीब लोगों को 5 लाख रुपये तक मुफ़्त इलाज कराने का दावा किया जबकि परिस्थितयां इसके बिल्कुल विपरीत हैं और वर्तमान में चिकित्सा सुविधा केवल 20 लाख लोगों के लिये भी नहीं है, जिसका 'चिकित्सा सुविधा नहीं 20 लाख के लिये भी बातें हैं 50 करोड़ तक पहुंचने की' में कच्चा चिट्ठा खोला गया है।

गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ़ मुकदमा चलाने सम्बन्धित दायर जकिया जाफ़री की याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई है। इस मामले में गठित एसआईटी जांच में एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ़ विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढाने समेत कई मामलों में मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसका 'मोदी के खिलाफ़ मुकदमा चलाने के पर्याप्त कारण गुजरात दंगा मामले में एमिकस क्यूरी ने दी थी रिपोर्ट' में खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट से गुजरात दंगा मामले के केस में एक दिलचस्प मोड़ आ गया।

गुजरात के पूर्व गृहमंत्री हरेन पांड्या हत्याकांड केस में भी एक नया मोड़ आ गया जब गवाह आजम खान ने अदालत को बताया कि ''हरेन पांड्या को मारने की सुपारी पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा ने सोहराबुद्दीन को दी थी''। हरेन पांड्या हत्याकांड में नए खुलासे के बाद पत्रकार प्रशांत ने जागृति को लिखा पत्र, कहा आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी' में वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल ने हरेन पांड्या की पत्नी जागृति को लिखे पत्र के माध्यम से इस हत्याकांड के पीछे राजनीतिक षडयंत्र की परतें उघेड़ने की कोशिश की है। यदि गवाह का यह बयान सत्य है तो इस हाई प्रोफ़ाइल हत्याकांड के तार देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जिसने वंजारा को इशारा किया है।

'पाच साल से बिना प्रिंसिपल के चल रहा डीएवी मैनेजमेंट कॉलेज-नीलम गुलाटी की योग्यता प्रोफ़ेसर की भी नहीं, रहना चाहती है प्रिंसिपल' में स्थानीय एचएच-3 स्थित डीएवी मैनेजमेंट कॉलेज में चल रही गड़बड़ घोटाले का भंडा फ़ोड़ किया गया है। एमडीयू के कुलपति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधी द्वारा पैनल में बैठने से इंकार करने से इंगित होता है कि कुलपति व हरियाणा उच्च शिक्षा आयुक्त हर हालत में नीलम गुलाटी को प्रिंसिपल के पद पर चयनित करने के लिये अनुचित व अनावश्यक दबाव बना रहे हैं और डीएवी प्रबंधन कमेटी लाचार होकर मूकदर्शक बनी हुई है। अहम प्रश्न है कि क्या नीलम गुलाटी इतनी योग्य, कुशल व ताकतवर है कि उसके बिना कॉलेज नहीं चल सकता?

'मोदी का नाम और बैंक कर्मी बदनाम-59 मिनट में लोन नहीं, दिसम्बर तक 1180 करोड़ का क्या होगा!' में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक का लोन देने की घोषणा के बाद बैंक अधिकारी व लोन मांगने वाले ग्राहक के बीच बढ़ती तकरार का विवेचन किया गया है। मोदी सरकार ने ग्रहक की वैरीफिकेशन का काम गुजरात के नवरंगपुर, अहमदाबाद में पंजीकृत ''कैपीटल वर्लड प्लेटफ़ार्म प्राइवेट लिमिटेड' निजी कम्पनी को दिया है जो बिना स्वीकृत हुये ही ग्राहक से 1180 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस ले लेगी, जबकि पहले यह काम अलग-अलग बैंक ब्रांच की विभिन्न एजेंसिया करती थी। कैसा लगता है कि मोदी के 59 मिनट प्रोजेक्ट के लिये ही इस निजी कम्पनी को बनाया गया जो 2015 में अस्तित्व में आई थी।

हरियाणा की शक्तिशाली क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल एक बार फ़िर विरासत की उठापटक की शिकार हो गइ है, जिसका 'चौटाला खानदान की नूरा कुश्ती...मांग रहे हैं कुछ सवालों के जवाब' में सटीक विश्लेषण किया गया है। अजय चौटाला व अभय चौटाला दोनों भाई दंगल में खुलकर आमने-सामने आ गये हैं। उनके समर्थक भी दो गुटों में विभाजित हो रहे हैं। अब सब की निगाहें 9 दिसम्बर पर है जब अजय चौटाला नई पार्टी के गठन की घोषणा करते हैं अथवा दोनों भाइयों में कोई सुलहनामा होता है।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूंजीपतियों अडानी व अंबानी को आर्थिक लाभ पहुंचाने पर श्रवण की तरह मोदी जी मां-बाप की जगह अडानी-अंबानी को बहंगी में बैठाकर ले जाते हुये 'अडानी-अंबानी', मोदी जी द्वारा अपने आपको जनता का चौकीदार कहने पर 'बिल्डर उद्योगपति, बीमा...तुझे गलतफहमी हुई है-वह तेरा नहीं हमारा चौकीदार है' तथा प्रधानमंत्री मोदी अक्सर झूठ बोलने पर 'प्रथम सेवक (नेहरू)....प्रथम झूठिया (मोदी)' कार्टूनों द्वारा उपयुक्त व्यंग्य किया गया है।